संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली से बम्बई, मद्रास तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली, बम्बई और कानपुर में ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों की स्थापना का कार्य पहले से ही प्रगति पर है। मद्रास स्थित ट्रंक स्वचल एक्सचेंज ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है तथा बंगलौर मद्रास मार्ग उसके माध्यम से काम कर रहा है। कलकत्ता में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को उपस्कर भेजने के लिए मांग पत्र भेज दिया गया है। ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों को चालू करने के लिए आवश्यकता पड़ने वाले लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध हैं किन्तु आने वाले वर्षों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के बढ़ते हुए परियात को निपटाने के लिए कई सूक्ष्मतरंग सहधुरीय। योजनाएं आयोजित की गई है जिनके लिए उपस्कर का आयात करना है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने की कठिनाइयों के कारण इन परिपथों की व्यवस्था करने में विलम्ब होने की संभावना है।

REPORT OF THE CHIEF ELECTION COMMISSIONER ON THE LAST GENERAL ELECTIONS

4891. SHRI SIDDAYYA: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) the important recommendations made by the Chief Election Commissioner in his Report regarding the 1967 General Elections; and

(b) whether any of them have been implemented so far?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM): (a) A summary of the main recommendations made by the Chief Election Commissioner in his Report on the Fourth General Elections, 1967, is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1824/68].

(b) No, Sir.

SHIFTING OF TELEPHONE TRUNK EXCHANGE OFFICE TO DHARWAR

4892. SHRI JAGANNATH RAO JOSHI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a demand from people to shift the Telephone Trunk Exchange Office to Dharwar from Hubli (Mysore-State); and

(b) if so, whether Government propose to shift the said exchange?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) A request from Shri Y. H. Patil, MLC, Mysore, was received by the Postmaster General, Mysore Circle.

(b) No.

मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में शरणार्थी परियोजना

4893. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में शाहापुर के समीप शरणार्थी परियोजना में 10′—12′ के कमरे में दो परिवारों को बसाया जाता है और इस छप्पर की झोपड़ी का मूल्य 2,000 रुपये नियत किया गया है तथा इस राशि को प्रत्येक झोपड़ी की कीमत के लिये, उनको दिये गये ऋण के रूप में दिखाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना में शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिये अथवा उनकी कृषि भूमि की सिचाई के लिये तथा शाहापुर से इस परियोजना तक सड़क बनाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शरणार्थियों द्वारा वहां अनेक कठिनाईयों का सामना किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) मध्य प्रदेश की बेतुल पुनर्वास परियोजना में, 376 जुड़वां झौपड़ियां जिनमें सामान्य दीवार को छोड़कर पृथक-पृथक दो कमरे हैं और प्रत्येक का माप $12'-6\frac{3}{4}'' \times 15'$ है, चौपना I, II और III, हीरापुर I तथा II पूंजी और कोलिया में निर्मित किये गये है । हीरापुर I तथा II पूंजी तथा कोलिया के प्रत्येक झौपड़े के साथ 6 फुट चौड़ा बरांडा भी बनाया गया है । ऊपर दिये गये आकार के एक कमरे में, पूर्वी पाकिस्तान से आये केवल एक प्रव्रजक परिवार को बसाया जाता है, इस प्रकार इन जुड़वां झौपड़ियों के प्रत्येक सेट में ऐसे दो परिवारों को बसाया जाता है । 376 जुड़वां झौपड़ियों के निर्माण पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7.25 लाख रुपये व्यय किये गये है . इस प्रकार जुड़वां झौपड़ी के प्रत्येक सेट पर औसत लागत लगभग 1,930 रुपये बनती हैं और प्रति परिवार 965 रुपये बनते है । सभी पुनर्वास योजनाओं में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, यह कुल राशि, सम्बन्धित प्रव्रजक परिवारों के लिये ऋण के रूप में समझी जायेगी ।

(ख) प्रव्रजक बच्चों की शिक्षा के लिये, परियोजना क्षेत्र में 6 प्राइमरी स्कूल तथा 2 माध्यमिक स्कूल स्थापित करने के लिये भारत सरकार द्वारा लगभग 1,00,000 रुपये का व्यय मंजूर किया गया है । इसके अतिरिक्त बेतुल में नये प्रव्रजकों के 183 बच्चों को छात्र वृत्तियों के रूप में अब तक 88,000 रुपये मंजूर किये गये है ताकि वे बेतुल तथा माना में अध्ययन जारी रख सकें । बरबतपुर से बेतुल पुनर्वास खंड तक पहुंचमार्ग बनाने के लिये 6,02,600 रुपये की धन राशि मंजूर की गई है । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना क्षेत्र में सिचाई सुविधाएं देने के लिये एक सिचाई परियोजना की योजना, जिसमें बिचवा नहर लतिया जलाशय इत्यादि है, तैयार की गई थी । इस योजना की छान-बीन भारत सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई है और उसके उपरान्त राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किये गये अवलोकन को ध्यान में रखते हुये योजना को परिशोधित किया जाये । राज्य सरकार से पुनरीक्षित योजना की प्रतीक्षा है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को याद दिलाई गई है ।

(ग) और (घ) . मध्य प्रदेश में रहने वाले नये प्रव्रजकों से, जिनमें बेतुल परियोजना में रहने वाले प्रव्रजक भी शामिल है, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जिन में सस्ते दामों पर चावल का दिया जाना, भरण-पोषण अनुदान को जारी रखना, विद्यालयों की व्यवस्था, तथा पहुंच-मार्गों इत्यादि के बारे में प्रार्थना की गई है ।

नकद बेकारी अनुदान की पूर्ण दर पर अनुदान के रूप में भरण-पोषण सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में पहले ही मंजूरी जारी कर दी गई है । वे नये कृषक परिवार जो 1968–69 के अन्तर्गत पहली बार अपनी खेती करेंगे उन्हें प्रथम जून, 1968 से सस्ते दामों पर चावल/गेहूं का राशन देने की मंजूरी भी दी जा चुकी है ।

उन नये प्रव्रजक कृषक परिवारों के लिये जो पिछले वर्षों में भूमि की खेती करते रहे थे, उपरोक्त अवधि के लिये पूर्ण बेकारी अनुदान की दरों पर केवल भरण-पोषण ऋण की मंजूरी दे दी गई

है। वे सस्ती दरों पर राशन प्राप्त करने के पात्र नहीं है।

जहां तक विद्यालयों इत्यादि का सम्बन्ध है, स्थिति का उल्लेख इस प्रश्न के भाग (ख) में किया गया है।

CENTRAL PLANT PROTECTION AND STORAGE, DHARWAR

4894. SHRI JAGANNATH RAO JOSHI: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government had opened a Central Plant Protection and Storage Station at Dharwar in Mysore State;

(b) the reasons for opening it at Dharwar and the total amount spent on it; and

(c) whether it is also a fact that the same has now been closed and if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) The entire country has been divided into 14 Agroclimatic regions and Dharwar area is one of them. The Station at Dharwar was opened in 1957 in consultation with the State Government to assist it with technical personnel, plant protection machines, pesticides and vehicles for control of pests and disease outbreaks until their own resources were developed. The total expenditure amounted to Rs. 8 lakhs only.

(c) This Station has been closed at Dharwar with effect from 8-8-1968, because suitable and adequate arrangements with regard to trained personnel, plant protection equipment and pesticides are now available with the Department of Agriculture, Government of Mysore, for Dharwar.

गायों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान

4895. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में राज्यवार कितनी गायों और भैंसों को कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भ धारण कराया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गर्मियों में उपरोक्त विधि से जिन भैंसों को गर्भाधान कराया गया था, उन्होंने गर्भ धारण नहीं किया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (ग). राज्यों/संघ क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली का चिड़िया-घर

4896. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चिड़िया-घर में रहने वाले प्राणियों के अस्वस्थ रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उसका एक कारण उनको अपर्याप्त तथा घटिया दर्जे का खाना दिया जाता है ;

(ग) क्या चिड़िया-घर के प्राणियों के लिये निर्धारित खाने की मात्रा में चिड़िया-घर के कर्मचारी गोल-माल करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?